गिलगिट बाल्टिस्तान, चीन और पाकिस्तान

*डॉ. ध्रुवज्योति भट्टाचार्य**

पाकिस्तान का जलाशय - गिलगिट-बाल्टिस्तान पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तानी संघीय सरकार के साथ-साथ चीन द्वारा प्रारंभ की गई राजनैतिक रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना कर रहा है। काराकोरम राजमार्ग के निर्माण, वर्ष 2009 के शासनादेश, जातीय हिंसा में वृद्धि और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में कुछ क्षेत्रों के वर्तमान समावेश के साथ ही गिलगिट-बाल्टिस्तान अत्यधिक अस्थिर बन गया है।

गिलगिट-बाल्टिस्तान - राजनैतिक इतिहास

पाकिस्तान का संविधान गिलगिट-बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी क्षेत्र में शामिल नहीं मानता, हालांकि सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही इस क्षेत्र पर संप्रभुता का प्रयोग किया है। बल्कि, गिलगिट-बाल्टिस्तान का उल्लेख एक ऐसे क्षेत्र के रूप में किया जाता है, जो पकिस्तान द्वारा प्रशासित है, लेकिन इसे (पाकिस्तान के) संविधान से बाहर रखा गया है।[1]

हालांकि यह क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल लगभग 72,496 वर्ग किलोमीटर है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तरी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था और इसके पश्चात वर्ष 2009 तक, इसे गिलगिट-बाल्टिस्तान अधिकारिता एवं स्वशासन आदेश, 2009, द्वारा गिलगिट-बाल्टिस्तान का नया नाम दिया गया। यह परिवर्तन उन कुछेक कृत्रिम परिवर्तनों में से एक था, जो पिछले सात दशकों में अधिकृत क्षेत्रों में किये गए थे। इस क्षेत्र को न तो प्रांत का दर्जा दिया गया था और न ही इसे लंबे समय से मांगी जा रही स्वायत्तता ही दी गई, जिसकी मांग स्थानीय जनता ने संघीय सरकार से की थी, जो अस्पष्टता तथा औपनिवेशिक विचार को दर्शाता है, जिसे पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इस क्षेत्र के संबंध में अपना रखा था। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने

लोकतांत्रिक स्वरूप को लागू न करने का निर्णय लिया और यह क्षेत्र कराची से, कश्मीर मामले मंत्रालय द्वारा शासित होता रहा।[2] यहां तक कि वर्ष 2009 के चुनावों के बाद भी स्थिति ज्यादा बदली नहीं है जहां (अब भी) इस क्षेत्र की अधिकांश नीतियों पर इस क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों की बजाय संघीय सरकार द्वारा निर्णय लिये जाते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के अनेक लोगों की राय है कि संघीय सरकार का यह आदेश विवादित क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने का षडयंत्र था।[3]

काराकोरम राजमार्ग अब भी गिलगिट-बाल्टिस्तान के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। वर्ष 1985 में इस राजमार्ग का निर्माण पूरा होने के बाद, पहले के उत्तरी क्षेत्रों (वर्तमान गिलगिट-बाल्टिस्तान) को पांच जिलों में बांटा गया था, नामतः गिलगिट, घीजर, डियामीर, स्कार्डू और घनची। गिलगिट-बाल्टिस्तान के प्रभारी मुख्यमंत्री शेर जहां मीर काराकोरम कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं, जो गिलगिट-बाल्टिस्तान में एकमात्र बैंक है।

आधिकारिक रूप से, पाकिस्तान ने इन आधारों पर गिलगिट-बाल्टिस्तान के एकीकरण की मांग को हमेशा ठुकराया है कि इससे कश्मीर विवाद पर इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता विपरीत रूप से प्रभावित होगी। संघीय सरकार शासी स्वरूप में एकरूपता लाने का प्रयास करते समय अपरिपक्व कदम उठाती प्रतीत होती है। इस क्षेत्र का दुरूपयोग इसके संसाधनों के लिए किया गया है; इसके भू-भाग चीनी जनवादी मुक्ति सेना (पीएलए) को सौंप दिया गया है, जहां पाकिस्तानी सेना तक की भी पहुंच नहीं है, जिससे एक ऐसे छद्म लोकतंत्र को समर्थन मिलता है, जो लोगों के सामान्य कल्याण तथा हितों को हानि पहुंचाती है। हालांकि, वर्ष 2009 के शासनादेश के कारण चुनाव हो सके और सैयद मेहदी शाह मुख्यमंत्री बन सके, फिर भी संघीय सरकार पुनर्मतदान अथवा कार्यवाहक सरकार के संबंध में विस्तारपूर्वक व्याख्या किए जाने की आवश्यकता को भांपने में असफल रही जो इस शासनादेश में शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री शरीफ़ को एक कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था संबंधी खंड सहित इस आदेश में विशेष संशोधन करने पड़े थे।

शिया-सुन्नी कारक

ऐतिहासिक रूप से, गिलगिट-बाल्टिस्तान के विविध समुदाय पूर्ण सद्भावना के साथ मिलकर रहते आए हैं।[4] सदियों के दौरान विकसित हुई जातीय तथा सामाजिक गठबंधन को सांप्रदायिक मेल-मिलाप से कहीं ज्यादा महत्व दिया गया है।[5] गिलगिट-बाल्टिस्तान की अनुमानित 13 लाख जनसंख्या में शिया सम्प्रदाय की बहुलता है। शेष पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय की बहुलता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में जिया-उल हक के काल से ही साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काया है, जब उन्होंने (जिया-उल हक ने) इस क्षेत्र में 'सुन्नी देवबंदी' इस्लाम लागू किया। एक सुन्नी देवबंदी लड़ाका समूह, सिपह-ए-सहाबा ने अन्य सुन्नी समूहों के साथ मिलकर तथा

इस राष्ट्र के सहयोग से इस क्षेत्र में सक्रिय घुसपैठ प्रारंभ करके, 'फसलों तथा घरों को नष्ट किया, सैकड़ों लोगों की हत्या की और जलाकर मौत के घाट उतार दिया।[6] कुछ विश्लेषकों ने यहां तक संकेत दिया है कि ऐसी साम्प्रदायिक हिंसा राष्ट्र द्वारा राजनैतिक हथियार के तौर पर उपयोग में लाई जाती थी, जिसकी सुविधा केवल काराकोरम राजमार्ग के निर्माण के बाद से मिलने लगी, जिसने पहले अलग-थलग पड़े इस क्षेत्र को चीन और मुख्य पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया।[7] उनका यह भी कहना था, "गिलगिट-बाल्टिस्तान को इसके भौतिक अलगाव से निकालने और आर्थिक अवसरों को प्रदान करने के साथ-साथ इस राजमार्ग ने गिलगिट-बालटिस्तान के लिए नए खतरों जैसे अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और दक्षिण के असहिष्णु व्यवहार के कारण ज्यादा असुरक्षित बना दिया, जिसने गिलगिट तथा अन्य शहरों की जनसांख्यिकीय स्थिति को बदल दिया है।"[8]

प्रारंभ में, साम्प्रदायिक तनाव केवल गिलगिट शहर तक ही सीमित था, जहां धार्मिक मुल्ला अपने-अपने पंथ के मस्जिदों से एक दूसरे के लिए अपमानजनक घोषणाएं करते थे और शिया-सुन्नी नौजवानों के बीच अति-उत्तेजना में, विशेषकर मुहर्रम के जुलूसों के दौरान, झगड़े हो जाते थे, जिन्हें स्थानीय बुज़ुर्गों द्वारा तुरंत नियंत्रित कर दिया जाता था। ऐसी साम्प्रदायिक हिंसा, जिसके कारण मानव जीवन की हानि हुई, का पहला मामला वर्ष 1975 में हुआ, जब गिलगिट शहर में शियाओं के मुहर्रम जुलूस पर सुन्नी मस्जिद से गोलियां बरसाई गईं। इसके बाद सुन्नी काज़ी (धार्मिक नेता) की गिरफ्तारी के कारण सिंधु घाटी, दक्षिण गिलगिट और गोर, दरेल और तंगीर की घाटियों के सुन्नी क्षेत्रों में दंगे भड़के। इन क्षेत्रों के सुन्नियों ने गिलगिट पर आक्रमण करने की धमकी दी।[9]

अगला बड़ा टकराव वर्ष 1983 में हुआ, जो चांद दिखने - एक ऐसा समय, जिसमें रमज़ान के एक महीने लंबे रोजे का अंत और ईद उत्सव का प्रारंभ होता है - को लेकर विवाद पैदा होने के कारण हुआ। शिया समुदाय ने अपने धार्मिक नेताओं द्वारा चांद देखे जाने की घोषणा के आधार पर रोजा तोड़ दिया और उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया, जबकि सुन्नी समुदाय अभी भी रोजा ही रख रहा था। यह मतभेद महत्वपूर्ण था क्योंकि मुसलमानों को ईद के दिन रोजा रखने की मनाही है। इससे तुरंत तनाव फैल गया और गिलगिट शहर में हिंसक झड़पें हुईं जिसमें दो लोग मारे गए और अनेक घायल हुए।[10]

इसके बाद से अनेक आंतरिक तथा बाह्य कारकों ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में जातीय संघर्षों को बढ़ाने में एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करने में योगदान दिया है। कुछ आंतरिक कारकों में शामिल हैं - पारम्परिक संस्कृति विशेषकर संगीत तथा नृत्य का ह्रास होना, बढ़ती सामाजिक तथा आर्थिक असमानता; और युवाओं के बीच

बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आन्तरिक प्रवास ने भी गिलगिट तथा अन्य शहरों की जनसांख्यकीय संरचना को परिवर्तित किया है। गिलगिट-बाल्टिस्तान की विवादित स्थिति और इस्लामाबाद से लंबे समय से प्रत्यक्ष शासन के कारण न केवल राजनैतिक भागीदारी के लिए सीमित अवसर मिले हैं और कुन्द सांस्थानिक विकास हुआ है, बल्कि इसने स्थानीय संसाधनों जैसेकि जलविद्युत तथा खनिजों के विकास को भी बाधित किया है। उभरती जनसंख्या और रोजगार के अवसरों के अभाव से भी साम्प्रदायिक हिंसा तथा अपराध को बढ़ावा मिलता प्रतीत होता है। बाह्य कारणों में मुख्य भूमि पाकिस्तान से असहिष्णु दृष्टिकोण का उत्तरोत्तर बढ़ना और अतिवादी साम्प्रदायिक हिंसा के अतिरिक्त प्रभाव शामिल हैं।[11]

वर्ष 2009 में चुने गए मुख्यमंत्री, सैयद मेहदी शाह, हालांकि स्वयं शिया समुदाय के थे, (पर वे) इस क्षेत्र में बार-बार होने वाली उग्र साम्प्रदायिक हिंसा को शांत करने में पूरी तरह विफल रहे। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना गया था, लेकिन उनके पास न तो अपने पुलिस प्रमुख को चुनने की कोई शक्ति थी और न ही बढ़ती हिंसा पर लगाम लगाने में वे सीमावर्ती टुकड़ियों, गिलगिट-बाल्टिस्तान स्काउट और अन्य संसदीय ताकतों का 'मार्गदर्शन' ही कर सके, क्योंकि इन सबने रावलपिंडी के आदेशों का पालन किया। बल्कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के बाद का अपना भविष्य सुरक्षित बनाने को चुना, स्वयं को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाया और मुख्यमंत्री पद से जुड़े सभी अधिकारों का लाभ उठाया।

वाशिंगटन स्थित गिलगिट-बाल्टिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस (जीबीएमसी) का कहना है कि साम्प्रदायिक अलगाव गिलगिट-बाल्टिस्तान में और शिया बहुल अन्य क्षेत्रों जैसे पराचिनार घाटी (खैबर पख्तूनख्वा में) राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रबंधन का चुना हुआ साधन रहा है। यह नीति सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल हक के काल की है जिसके उत्तराधिकारियों ने, जीएनबीसी के अनुसार, इन रणनीतिक क्षेत्रों को खाली करने के लिए शिया बहुल जनता पर दबाव डालकर जनसांख्यकीय परिवर्तन हासिल करने की नीति को बेहतर बनाया है।[12]

चीन कारक

गिलगिट-बाल्टिस्तान में चीन की भूमिका न केवल काराकोरम राजमार्ग के निर्माण के कारण, बल्कि कई अन्य कारकों के कारण महत्वपूर्ण बनी हुई है। उईघर शरणार्थियों का मुद्दा, जिन्हें काशगर के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्पीड़ित[13] किये जाने के डर से चीन के झिंझियांग प्रांत से भागकर गिलगिट-बाल्टिस्तान में आ बसे हैं; शियाचीन ग्लेशियर से निकटता; और इस क्षेत्र के अफ़गान तालीबान के लिए गिलगिट-बाल्टिस्तान का एक नए आश्रय में बदलना ऐसे कारण हैं, जो इस क्षेत्र को चीनी नीति-निर्माताओं के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं।

तीन प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, काराकोरम और हिंदूकुश इस क्षेत्र में आकर मिलते हैं। संमिलन के इस क्षेत्र के निकट चीनी तीन बड़े-बड़े डैम का निर्माण कर रहे हैं। गिलगिट-बाल्टिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में 30,000 मेगावाट से भी अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता है। इनमें से सबसे बड़ी सिंधु नदी है, जो पाकिस्तान के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत भी है। तथापि, निर्माणाधीन और विचाराधीन डैम इन घनी आबादी वाली घाटियों के बहुत बड़े हिस्सों को जलप्लावित कर देंगे।[14]

सिंधु नदी पर दियामर-भाषा डैम का निर्माण 18 अक्तूबर 2011 को प्रारंभ हुआ। इसके पूरा हो जाने के बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा रौलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (आरसीसी) डैम होगा और इसके द्वारा 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने, पाकिस्तान के लिए 8,500,000 एकड़ फीट (10.5 किलोमीटर) जल संग्रह करने की आशा है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा पीने के लिए किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 11 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक है और इसके पूरा होने का अनुमानित समय 12 वर्ष है। भूकंप की अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र में इसकी अवस्थिति स्थानीय जनता के लिए बड़ी चिंता का कारण है, जो इस निर्माण के सभी विपरीत परिणामों का सामना करेंगे, जबकि सभी लाभ पंजाब और सिंध में रहने वाले लोगों को मिलेंगे। स्काई कस्बा जहां 100,000 लोगों से अधिक की जनसंख्या है, की अनदेखी सतपाड़ा डैम द्वारा की गई है। अप्रैल 2003 में प्रारंभ हुई इस परियोजना से 17.6 मेगावाट बिजली के उत्पादन की संभावना है। इस डैम का विरोध स्थानीय पत्रकारों और कार्यकर्ताओं द्वारा इसके दोषपूर्ण डिज़ाइन और सामग्री के कारण किया जाता है, जिसका परिणाम विस्फोटक हो सकता है, जिससे स्काई घाटी के निवासी प्रभावित होंगे।[15]

अब तक, गिलगिट-बाल्टिस्तान में दर्जनों स्थानीय लोग जवाहरातों, यूरेनियम, सोना, तांबा और भारी धातुओं से संबंधित चीनी खनन परियोजनाओं का विरोध करने के कारण राजद्रोह के आरोप, गिरफ्तारी और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। चीनी फर्मों के विरूद्ध रोज़गार तथा वित्तीय मुआवजा देने से मना करने तथा खेती योग्य भूमि और बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें हैं। तुर्की और मलेशिया में वर्तमान में काली सूची में डाली गई एक चीनी फर्म, चीन सड़क एवं पुल निगम पर अनेक लोग गिलगिट-बाल्टिस्तान में काराकोरम राजमार्ग के विस्तार करने में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने के तरीकों का उपयोग करने का आरोप लगाते हैं।[16] स्थानीय समाचार पत्र, दैनिक *बादेशिमल* ने उल्लेख किया कि चीनी फर्में स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं और ये क्षेत्रीय विकास में योगदान करने में असफल हैं।[17] हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के उपमहानिदेशक ह्वांग जिलियांग ने कहा, "ये परियोजनाएं राजनैतिक परियोजनाएं नहीं हैं। ये सभी लोगों की आजीविका के लिए हैं। इस क्षेत्र के उस भाग में चीन द्वारा कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं चलाई जाती।" जिसमें गिलगिट-बाल्टिस्तान के आम लोगों की बदहाली की अनदेखी की गई प्रतीत होती है।[18]

अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक, सेलिंग हैरिसन ने कहा कि पाकिस्तान ने वस्तुतः गिलगिट-बाल्टिस्तान को चीन को सौंप दिया है। "गिलगिट-बाल्टिस्तान में प्रवेश करने वाले अनेक जनवादी मुक्ति सेना (पीएलए) के सिपाहियों से रेलमार्ग पर काम करने की आशा की जाती है। कुछ चीन के सिंकियांग प्रांत को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे कराकोरम राजमार्ग का विस्तार कर रहे हैं। कुछ अन्य डैम, एक्सप्रेसवे तथा अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "गुप्त स्थानों पर 22 सुरंगों का निर्माण रहस्य से घिरा है, जहां पाकिस्तानियों को जाने की मनाही है। ईरान से चीन तक प्रस्तावित गैस पाइपलाइन के लिए सुरंग आवश्यक होंगे जो गिलगिट से होकर हिमालय को पार करेंगे। लेकिन इनका उपयोग मिसाईल संग्रहण स्थलों के रूप में भी किया जा सकता है....। हाल तक जनवादी मुक्ति सेना (पीएलए) के निर्माण कर्मचारी अस्थाई शिविरों में रहते थे और अपने नियत कार्यों को पूरा करने के बाद घर चले जाते थे। अब वे बड़े रिहायशी इनक्लेवों का निर्माण कर रहे हैं, जो स्पस्ट रूप से दीर्घकालिक उपस्थिति के लिए तैयार किए गए हैं।"[19]

राजमार्ग के निर्माण के दौरान पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की उपस्थिति ने न केवल पाकिस्तानी पड़ोस में गंभीर संदेह उत्पन्न किये हैं, बल्कि गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोगों में भी चीनियों द्वारा कब्ज़ा किये जाने के संदेह हैं। इस राजमार्ग का प्रयोजन अधिकांश विदेशी विश्लेषकों को स्पष्ट था क्योंकि वर्ष 2010 में ही कहा गया था कि चीन ने काराकोरम राजमार्ग पर 15,397 फीट खुंजेराब दर्रे पर पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की थल सेना की एक टुकड़ी की तैनाती एक रेलमार्ग के निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों की सुरक्षा के लिए की है। यह रेलमार्ग अंततः झिंझियांग को बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वाधर पत्तन से जोड़ेगा,"[20] जो आज का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है।

हैरानी की बात है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने बलूचिस्तान में हिंसा तथा विद्रोह पर चिंता जताई है, जो सीपीईसी परियोजना में बाधा डाल सकता है और पाकिस्तानी सेना द्वारा तैयार किया गया नौ बटालियन वाला सुरक्षा बल मुख्य रूप से केवल बलूचिस्तान के लिए है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के संबंध में स्थानीय जनता में साम्प्रदायिक हिंसा अथवा चीन विरोधी भावनाओं के उभरने के संबंध में ऐसी कोई आशंका नहीं जताई गई है, क्योंकि जनवादी मुक्ति सेना (पीएलए), सैन्य न्यायाधिकरण के सहयोग से विद्रोह अथवा बगावत की ऐसी आवाज़ों को आसानी से दबा देने की आशा रखती है।

गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव

प्रारंभ से ही पाकिस्तान इस क्षेत्र को संवैधानिक वैधता प्रदान करने में अत्यधिक कतराता रहा है और इसने यह मानने में अनेक वर्ष लगा दिए कि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की अनदेखी किये जाने की बजाय उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक के साथ-साथ राजनैतिक विकासात्मक प्रक्रिया में पाकिस्तान

अधिकृत संपूर्ण कश्मीरी क्षेत्रों की अत्यधिक अनदेखी की गई है।

पाकिस्तान के चार प्रांतों के साथ-साथ चार गैर-प्रांतीय एकक भी हैं, जिनके नाम फाटा (संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र), उत्तरी क्षेत्र (जिसे अब गिलगिट और बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है), पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का शेष भाग और इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र हैं। गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोग 60 वर्षों से भी अधिक समय से संवैधानिक शून्यता में रहते आ रहे हैं, क्योंकि संसद में न तो उनका कोई प्रतिनिधि है और न ही स्थानीय विधानमंडल के लिए अनिवार्य संवैधानिक दर्जा ही दिया गया है।

29 अगस्त, 2009 को पाकिस्तान सरकार ने "गिलगिट-बाल्टिस्तान अधिकारिता एवं स्वशासन आदेश, 2009" की घोषणा की। 9 सितंबर, 2009 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित इस आदेश, जो कि 1970, 1975 और 1994 के पूर्ववर्ती सुधारों से तैयार किया गया है, ने प्रशासनिक, राजनैतिक, वित्तीय और न्यायिक सुधारों को आरम्भ किया।

वर्ष 2009 का आदेश गिलगिट-बाल्टिस्तान के लिए प्रशासन की निम्नलिखित प्रणालियां स्थापित करता हैः

- गिलगिट-बाल्टिस्तान परिषद;
- विधान सभा;
- सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री (विधानसभा द्वारा इसके सदस्यों में से बहुमत द्वारा चयनित) और मंत्रीगण; और
- राज्यपाल, प्रधानमंत्री की सलाह पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा चयनित।

तथापि, आजकल संवैधानिक आधार के अभाव के कारण सभी न्यायिक मामले, जिन्हें गिलगिट-बाल्टिस्तान में सैन्य न्यायाधिकरणों में निपटाया जाता है, राजनैतिक उद्देश्य के आधार पर निपटाए जा रहे हैं। सैन्य न्यायाधिकरण, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, एक कायकारी आदेश द्वारा स्थापित किये गए थे। गिलगिट-बाल्टिस्तान में विस्तार तथा कब्ज़े को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यकारी आदेशों के उपयोग का एक लंबा इतिहास है। अतीत में इस्लामाबाद ने इनका उपयोग कठोर सीमावर्ती अपराधी विनियमन (ड्रैकोनियन फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन), जनरल जिया का मार्शल लॉ, शरिया न्यायालयों के साथ-साथ गिलगिट-बाल्टिस्तान में आतंकवाद विरोधी न्यायालयों की स्थापना के लिए किया। कार्यकारी आदेश बिना विधिवत प्रक्रिया अथवा मुआवज़ा के स्थानीय संसाधनों के विनियोजन के लिए नियमित तौर पर जारी किये जाते हैं। इनका उपयोग इस क्षेत्र के सैन्य रक्षक सेनाओं को ठहराने के लिए भी किया जाता है, जो कश्मीर तथा गिलगिट-बाल्टिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र संकल्पना का सीधा उल्लंघन है।

गिलगिट-बाल्टिस्तान में पहली बार 2009 में चुनाव हुए थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के उम्मीदवार सैयद मेहदी शाह की जीत हुई थी। पीपीपी पार्टी ने 23 सीटों में से ग्यारह, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेन्ट (एमक्यूएम) ने एक, पीएमएल (एन) ने दो, जमायत उलेमा-ए-इस्लाम ने एक, पीएमएल (क्यू) ने एक सीट जीता और चार सीट स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा जीते गए थे।[21]

विधानसभा में 33 सीट हैं जिनमें से 24 पर सीधा चुनाव लड़ा जाता है। वर्तमान चुनाव 8 जून, 2015 को होने तय हुए थे, लेकिन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) के मुख्य समन्वयक अहमद रज़ा खान कसूरी के साथ-साथ पीपीपी के पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अख्तर ने इन चुनावों के लिए जारी अधिसूचना को अवैध घोषित करते हुए पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभा चुनावों को चुनौती दी।[22]

तथापि, नियत तारीख को चुनाव हुए और इसके परिणाम ठीक वैसे ही आए, जैसी आशा राजनैतिक विश्लेषक कर रहे थे। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार, पीएमएल-एन ने 24 चुनाव क्षेत्रों में से 12 प्राप्त किए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफ (पीटीआई), मजलिस-ए-वहदत-मुसलमीन और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने दो-दो सीटें हासिल कीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलेमा-ए-इस्लाम और इस्लामी तहरीक ने एक-एक सीट जीता।[23]

यद्यपि, चुनावों में धांधली के आरोप लगाए गए थे और अनेकों ने चुनावी प्रक्रिया की उदासीनता पर सवाल उठाए, तथापि पीएमएल (एन) का आना अप्रत्याशित नहीं था। कुछ विश्लेषकों ने पीपीपी नेता सैयद मेहदी शाह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार तथा हिंसा का उल्लेख किया, जिसने जनता को पीपीपी से दूर कर दिया, लेकिन यह अंदाज़ा भी आसानी से लगाया जा सकता है, जब शरीफ़ के पीएमएल (एन) द्वारा संघीय सरकार चलाई जा रही हो और गिलगिट-बाल्टिस्तान इस्लामाबाद तथा कराची के कार्यालयों द्वारा, तो पीपीपी सरकार बनाने के लिए सर्मथन जुटाने में सफल कैसे होगी? वर्ष 2009 में भी यही तस्वीर थी, जब पीपीपी सत्ता में थी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी (कनाडा अस्थानी) के अध्यक्ष, मुमताज़ खान ने चुनावों से पहले कहा, "यदि आप गिलगिट-बाल्टिस्तान अथवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में विगत चुनावों के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पाऐंगे कि यह हमेशा उस पार्टी के पीछे जाती है जो इस्लामाबाद में है। वही पार्टी वहां आम तौर पर जीतती है और सरकार बनाती है। तथापि सैन्य सुझाव हमेशा मांगी जाती है विशेषकर वहां मुख्यमंत्री के नामांकन के संदर्भ में।"[24]

एक बात समझने योग्य है कि आने वाले दिनों में गिलगिट-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान सरकार द्वारा इस क्षेत्र में स्थिरता तथा शांति बनाए रखने के संबंध में उठाए गए निरूत्साहपूर्ण कदम के कारण गंभीर कठिनाईयों का

सामना करना पड़ेगा और जिस तरीके से इसने इस संपूर्ण क्षेत्र की विविध जनसंख्या के कल्याण को कठपुतली सरकार और उत्साही चीनियों की दया पर छोड़ दिया है। जबकि चीनी अपने "मुख्य क्षेत्रों को" प्रदर्शित करते हैं, उन्हें समझना होगा कि भारत के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी इसका "मुख्य क्षेत्र" है।

भारतीय दृष्टिकोण से गिलगिट-बाल्टिस्तान के क्षेत्र का उपयोग कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा सीधे तौर पर किया गया था, जिसने इसे ऑपरेशनल बेस के रूप में उपयोग किया। फिर भी वर्षों बाद जबकि रणनीतिक गणनाएं और प्राथमिकताएं बदल रही हैं, गिलगिट-बाल्टिस्तान को रणनीतिक और राजनैतिक दोनों प्रकार से सावधानीपूर्वक देखने और समझने की आवश्यकता है।

***

** डॉ. ध्रुवज्योति भट्टाचार्य विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*

समाप्ति नोट:

[1] आईयूसीएन, *पाकिस्तान में पर्यावरण कानून: प्राकृतिक संसाधनों और प्रक्रियाओं और संस्थाओं को शासित करना जो उन्हें प्रभावित करते हैं: उत्तरी क्षेत्र* (कराची, पाकिस्तान: आईयूएनसी पाकिस्तान, 2004), पृ. 17, जैसा कि केली होन्ग, " गिलगिट-बाल्टिस्तान में अंतिम सीमा (लिमिनालिटी) और प्रतिरोध", सत त विकास के लिए कानूनी सशक्तिकरण पर कानूनी आधार-पत्र श्रृंखला अंतरराष्ट्रीय सतत विकास कानून केन्द्र, क्यूबेक, 2012, पृ. 6.

[2] ओवेन बेनेट जोन्स, *पाकिस्तान: तूफान* की आँख (नई दिल्ली: पेंगुइन बुक इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, 2002), पृ. 70 बंसल आलोक द्वारा यथा उद्धृत "गिलगिट-बाल्टिस्तान: एक मूल्यांकन", मानेकशॉ पेपर, सं. 37, 2013, लैंड वारफेयर अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली, http://www.claws.in/images/publication_pdf/1365575414MP%2037%20inside.pdf.

[3] 'जी बी पैकेज के खिलाफ जेकेएलएफ मार्च", डॉन, *2 नवम्बर, 2009, http://www.dawn.com/news/944453/jklf-march-against-gb-package*

[4] मायरा इमरान, "गिलगिट-बाल्टिस्तान की सच्ची संस्कृति", *द न्यूज*, 10 जून, 2011, www.thenews.com.pk/Todays-News-6-51720-True-culture-of-Gilgit-Baltistan.

[5] इज़हार हुन्ज़ाई, " गिलगिट-बाल्टिस्तान में संघर्ष की गतिशीलता", संयुक्त राष्ट्र शांति संस्थान, विशेष रिपोर्ट, जनवरी 2013, पृ.4, http://www.usip.org/sites/default/files/SR321.pdf

[6] आलोक बंसल, "गिलगिट-बाल्टिस्तान: एक मूल्यांकन", मानेकशॉ पेपर, सं. 37, 2013, लैंड वारफेयर अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली, http://www.claws.in/images/publication_pdf/1365575414MP%2037%20inside.pdf.

[7] इज़हार हुन्ज़ाई, पृ. 5.

[8] पूर्वोक्त।

[9] मैगनस मार्सडेन, "स्वयं एवं अन्य : इस्लाम और पाकिस्तानी समाज में गिलगिट और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में मतभेद की बहुलता *का प्रतिनिधित्व": मानवविज्ञानी दृष्टिकोण*, संपा. मैगनस मार्सडेन और अली खान (कराची: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011), पृ. 240; मुहम्मद फैय्याज, "गिलगिट बाल्टिस्तान में सांप्रदायिक संघर्ष" (पृष्ठभूमि लेख, पाकिस्तान विधान विकास और पारदर्शिता संस्थान, लाहौर, मई 2011), पृ. 14, www.pildat.org/publications/publication/Conflict_Management/GB-SectarianConflit-BackgroundPaperEngMay2011.pdf

[10] हरमन करुट्ज़मैन, "कश्मीर और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र: विवादास्पद सीमाक्षेत्रों में सीमा-निर्माण,' *भूगोल*, खण्ड l. 62, सं. 3, 2008, पृ. 216.

[11] अब्दुल म लिक और इज़हार अली हुन्ज़ाई, "पहाड़ी क्षेत्रों में सतत विकास के लिए बहुलवाद के वायदे और चुनौती" (अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत लेख"विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीतियां

मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्र, "दुशान्बे, ताजिकिस्तान, 6-10 जून, 2005), www.akdn.org/ publications/2005_akf_mountains _paper11_english.pdf.

[12] मल्लादी रामा राव, "गिलगिट में पाकिस्तान के महान खेल", द डेमोक्रेसी फोरम *22 अप्रैल, 2013, http://thedemocracyforumltd.com/pakistans-great-game-in-gilgit/*

[13] शब्बीर मीर, "विस्थापित सपने : उइघुर परिवारों है पास गिलगिट-बाल्टिस्तान में घर जैसी कोई जगह नहीं", *द एक्सप्रेस ट्रिब्यून,* 21 मई , 2015, http://tribune.com.pk/story/889640/displaced-dreams-uighur-families-have-no-place-to-call-home-in-g-b/

[14] प्रियंका सिंह, "गिलगिट बाल्टिस्तान: आशा और निराशा के बीच", *आईडीएसए,* आईडीएसए मोनोग्राफ श्रृंखला सं 14, मार्च 2013, पृ. 58

[15] सेंगे सेरिंग, "गिलगिट-बाल्टिस्तान: एक अवलोकन", *स्कॉलर वैरियर,* क्लाॅंज, स्प्रिंग 2012, पृ. 65

[16] सेंगे सेरिंग, "चीन गिलगिट-बाल्टिस्तान में एक चौराहे पर ", गिलगिट-बाल्टिस्तान अध्ययन संस्थान, शरणोफ़्फ ग्लोबल व्यूज, 15 सितंबर, 2014, http://www.sharnoffsglobalviews.com/china-crossroads-baltistan-391/.

[17] पूर्वोक्त।

[18] "वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्पष्टता पर चीन ने भारत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया", *http://www.dailypioneer.com/todays-newspaper/china-rejects-indias-proposal-on-lac-clarity.html द पायोनियर,* 5 जून, 2015

[19] सेलिंग एस हैरिसन, "पाकिस्तान के उत्तरी सीमा पर चीन की विचारशील पकड़", *http://www.nytimes.com/2010/08/27/opinion/27iht-edharrison.html?_r=0 द न्यू यॉर्क टाइम्स,* 26 अगस्त, 2010

[20] "पुन: पाकिस्तान के उत्तरी गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीनी टुकड़ियों के बारे में एनवाईटी वृतांत", *द ग्लोबल इंटेलिजेंस फाइल्स*, विकिलिक्स, नवम्बर 2013, ' https://wikileaks.org/gifiles/docs/12/1221974_re-nyt-story-about-chinesetroops-in-pakistan-snorthern.html.

[21] "गिलगिट-बाल्टिस्तान के चुनावों में 23 में से 11 सीटों के साथ पीपीपी की बढ़त", जीयोटीवी, गिलगिट बाल्टिस्तान चुनाव 2009, 12 नवम्बर, 2009, http://www.geo.tv/important_events/2009/gilgit_baltistan_election/pages/english_news_12-11-2009.asp.

[22] "अधिकारों का उल्लंघन: गिलगिट-बाल्टिस्तान चुनावों के खिलाफ एक और याचिका दायर" , जी-बी वोट: गिलगिट-बाल्टिस्तान, आधिकारिक वेबसाइट, 5 जून, 2015, http://www.gbvotes.pk/english/infringement-of-rights-another-petition-filed-against-gilgit-baltistan-elections/.

[23] शब्बीर मीर, "गिलगिट-बाल्टिस्तान चुनाव: पीएमएल-एन ने विधानसभा की सीटों में से आधी हथियाई", *द एक्सप्रेस ट्रिब्यून,* 9 जून, 2015, http://tribune.com.pk/story/900299/gilgit-baltistan-polls-pml-n-grabs-half-of-assembly-seats/

[24] आर सी गंजू, "गिलगिट-बाल्टिस्तान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संभावनाएं नहीं", *भारत नीति,* 29 मई , 2015, http://www.bharatniti.in/story/chances-of-free-and-fair-elections-in-gilgit-baltistan-unlikely/33..